(b) if so, the details thereof;

(c) the established conventions to stipulate the royalty rates; and

(d) by when the rates of royalty are proposed to be revised?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) and (b) In addition to royalty on coal, several State Governments had in the past imposed cesses on coal. The Acts imposing such cesses had been struck down by the Supreme Court and the High Courts except in the case of West Bengal the Acts of the State are pending the decision of the Supreme Court. As the cesses in West Bengal are levied at a rate much higher than the royalty on coal, the rates of coal royalty introduced in August, 1991 are continuing in the State of West Bengal. A representation from the Government of West Bengal requesting for the extension of coal royalty at the current rates has been received.

(c) Since 1968 the royalty rates on coal have been stipulated on tonnage basis.

(d) The mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 does not contemplate the automatic revision of royalties on minerals after any specified period.

Revision in the rates of royalty on coal

.437. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Study Group set up for revision in the rates of royalty on coal has submitted its report; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) and (b) The Ministry of Coal had constituted a Study Group on 28.1.97 to interact with the coal producting States and the consuming bodies and to submit a report on the matter for assisting the Government in considering a revision in the rates of royalty. The Study Group has submitted its report. The recommendations of the Group are under consideration of the Government.

गुजरात को कोयले की आपूर्ति

438. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों और रेलवे के लिए कोयले की वार्षिक मांग कितनी रही है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों को कोयले की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों को इनकी मांग के अनुरूप कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में इन सबको उनकी आवश्यकतानुसार कोयले की आपूर्ति किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री दिलीप राय): (क) और (ख) गुजरात में कोल इंडिया लि. के साथ संयोजित कोई कोयला आधारित इस्पात संयंत्र नहीं है। रेलवे की आपूर्ति हेतु को,इ.लि. के स्रोतो की भी मांग नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कोयले की विद्युत तथा सीमेंट क्षेत्रों में मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

('000 टन में)

वर्ष	विद्युत		सीमेंट	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1995-96	15120	13684	1239	377
1996-97	14025	13806	944	345
1997-98 (अनं.)	15150	16012	382	39

(ग) और (घ) गुजरात में विद्युत क्षेत्र को की जाने वाली कोयले की आपूर्ति न्यूनाधिक रूप से स्वीकृत संयोजन के आधार पर की जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान आपूर्ति, संयोजन से अधिक था। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आपूर्ति संयोजन से थोडा कम था।

गुजरात के सीमेंट संयंत्र, स्वीकृत संयोजन के अनुसार कोयला प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोयले के संचलन संबंधी कार्यक्रम को भी प्रस्तुत नहीं किया है। गुजरात